

मौजूदा दौर में भारत-चीन संबंधों की तार्किकता

ज्यात मल्हात्रा

नाशता दल्ला म, दापहर का भाजन लाहर म और रोत का खाना काबुल में, क्या कोई कर सकता है? दक्षिण एशिया के लोगों के बीच सीमाओं को मिटाने का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिया बहुचर्चित नारा आज भी जीवंत और सटीक है - फर्क केवल इतना है कि इस पर अमल चीनी विदेश मंत्री वांग यी कर रहे हैं। गत हफ्ते की शुरुआत में यहीं हुआ। जब भारत बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर बने विवाद और विपक्षी कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 'वोटों की चोरी' के आरोपों में उलझा पड़ा था, उस बीच चीनी नेता राष्ट्रीय सुक्ष्मा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा वार्ता के एक और दौर के लिए दिल्ली आए। वांग ने प्रधानमंत्री मोदी को इस महीने के अंत में चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया- जिसको प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। इसके बाद वांग यी तालिबान से मिलने और अपने पाकिस्तानी एवं अफगान समकक्षों के साथ त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए काबुल पहुंचे। वहां से वे अपने 'आजमाया हुआ लौह बंधु' के साथ चीन की सामरिक साझेदारी का चर्चन दोहराने इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान पहुंचे। एक ही में दिन में तीन देशकुमानों ने मनमोहन सिंह की कही पर अमल कर रहे हों, फिर क्या हुआ अगर कुछ गंतव्य स्थल अलग रहे। वांग यी की यात्रा ने पाकिस्तान के गृह मंत्री को यह कहने का मौका दिया कि उनके देश के पास ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बायु सेना द्वारा भारतीय विमानों को मार गिराए जाने के बीड़ियों फुटेंज हैं। क्या यह पाकिस्तानियों का सरासर झुट है? लाजिमी है भारतीयों को यहीं उम्मीद है। भारतीय बायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हमें बताया है कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय बायुसेना ने पांच पाकिस्तानी जेट विमानों को मार गिराया है। हालांकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान पहले ही स्वीकार चुके हैं कि टकराव में भारत को भी कुछ हवाई सैन्य नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने जहजा। तीन महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस विषय पर चुप्पी है। वस्तु स्थिति जानना निश्चित रूप से अच्छा होगा।



پاکیستان پر سیرخ 19 پ्रतیشان ٹائیکن لگایا گیا ہے۔ بھارت د्वारा یہ ماننے سے انکار کر دیا کی تھے اور یا نی امریکا نے مई میں بھارت-پاکیستان سंबंध میں شانتی س्थاپنا کرવائے میں بھیمیکا نیبھاہی ہی، سافاک ہے کی تھے کی جا راجہی یہیں سے ہے۔ اسی وچہ سے وہی امریکی احیکاریوں نے بھارت اور بھارتی یہ کی پہنچوں پر روسی تلہ کی خیرید سے 'مُناکھوڑی' کرنے کا آراؤپ جڈا ہے۔ آسماں گھرہاتا دیکھ ویدے شہزادی اس سے جیشانکر روس گا، جہاں روس نے بھارت کو دیکھ جانے تلہ کی کیمتوں میں اور کٹائی کا پرسٹاک دیا ہے وہیں اچھی خبر یہ ہے کی بھارت سرکار کے دیل میں پونسٹولن کی س्थیتی بن رہی ہے۔ اک لانے ارسے تک، پیچلے اک دشک سے جیتا، بھارت د्वारा امریکا کی ترک بنتا جو کا وہ یہیکے اندھے گنبدیوں کی کیمپ پر رہا۔ اسے آراؤپ کوئی نہ بات نہیں ہے - بھارت کا کھلیں وہیں لانے سماں سے نیویوک اور ویشنگٹن ڈیسی کے بہترین ریسٹریٹ میں چھانے-پینے کا لوتک لےتا آیا ہے اور اسکے بچھے آیکی لیگ ویشیویالیوں میں پدھے ہیں؛ مودی کے کارکنکال میں بھی یہ س्थیتی شاہید ہی الگ رہی ہے۔

انتراریتی پتل پر اندھے پرمخ شکیوں کی اندرے ہی کے

अपना समय निकालना होगा - क्योंकि पहिए का फिर से धूमना तय है। इस पुनर्संथापना का एक दिलचस्प पहलू यह है कि भारत अमेरिका से भी संपर्क साथे रखेगा। अमेरिका इतना शक्तिशाली है कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और उससे दुश्मनी घातक है; निश्चित रूप से आप अमेरिकियों को अपनी तरफ रखना चाहेंगे, जैसा कि फ़ील्ड मार्शल असीम मुनीर बखूबी जानते हैं (पाकिस्तानियों को अमेरिका में एक शक्तिशाली पैरवीकार मिल गया है, जिसमें ट्रंप का एक पूर्व अंगरक्षक भी शामिल है, जिसने बाद में व्हाइट हाउस में भी काम किया है)। और जैसा कि यूरोपीय नेताओं के समूह को करते पाया जब वे यूक्रेनी राष्ट्रपति का हौसला बढ़ाने के लिए ट्रंप की मेज पर पहुंचे- अमेरिकी राष्ट्रपति की मनुहार उस सुबह एक कवायद थी। यही बजह है कि आगे महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाने पर मोदी ट्रंप से मिलना चाह रहे हैं। और इस यात्रा से पहले भारत ने अमेरिकी कपास पर लगाया जाने वाला 11 प्रतिशत आयात शुल्क निलंबित कर दिया है-ताकि भारतीय कृषि बाजार को और अधिक खोलने से इनकार करने से पैदा हुआ अमेरिका का गुस्सा कुछ शांत हो सके।

फैला है। ठग आपको फँसाने में लगे हैं, ऐसे में किस मैसेज को सही माना जाए, किसे गलत यह कैसे पता चले। अभी परिवहन विभाग का मैसेज आया है कि आधार आधारीड़जेशन माध्यम से अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराइए। समझ नहीं आ रहा कि क्या-क्या कराएं। हम पर ये सब करना नहीं आता। इसका मतलब ये की रोज जनसेवा केंद्र पर जाइये। लाइन में लगिए और पैसा भी दीजिए। लगता है कि कहीं ये जनसेवा केंद्र की आय बढ़ाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। अभी पिछले दिनों आदेश आया कि अपना आधार कार्ड प्रत्येक दस साल में अपडेट कराना है। मैं छोटे शहर में रहता हूं। यहां कि आबादी दो लाख के करीब है। पूरे शहर में आधार कार्ड अपडेट कराने का एक ही सेंटर है। मुख्य डाकघर। उसमें आधार कार्ड बनवाने वालों की संखे आठ बजे से लाइन लग जाती है। हम 75 साल से ऊपर के पति-पत्नी कैसे उस लाइन में लगें, ये कोई सोचने और बताने वाला नहीं है। दूसरे केंद्र का दरवाजा खुलने पर इस तरह धक्का-मुक्की होती है कि हम लाइन में लगे तो हाथ-पांव तुड़ाकर जरूर अस्पताल जाएंगे। केंद्र सरकार / रिजर्व बैंक को आदेश करना चाहिए कि बैंक अपने यहां अतिरिक्त स्टाफ रखे। उसके कार्य सिर्फ खाते धारकों से समय लेकर उनके खातों की केवाईसे कराना हो।

આમ જાપન સરલ બનાન મ મદ્દ કાર્ય

सरकारों का ल

तकनाक क माध्यम स उस एसा सुविधाएँ दना ह क वह परशन न हो, किंतु भारत में हो इसके विपरीत रहा है। उन्हें अलग-अलग काम के लिए थोड़ी- थोड़ी बात के लिए परेशान किया जा रहा है। उनके जीवन को दुर्घट किया जा रहा है। आज सबसे बड़ी परेशानी हैं बैंकों में जाकर खाते की केवाईसी कराने की। बैंकों की केवाईसी के नाम पर बैंक खाताधारक को परेशान किया जा रहा है। हालत यह है कि केवाईसी करानी है, इसकी उसे सूचना भी नहीं मिलती। उसे उसके लिए बैंक की ओर से मैसेज भी नहीं आता। मैल आनी चाहिए। किंतु ऐसा हो नहीं रहा। वैसे प्रत्येक ट्रांजेक्शन के मैसेज आते रहते हैं। केवाईसी कराना है, इसका पता तब चलता है जब खातेधारक के चैक का भुगतान रोक दिया जाता है। वह पेमेंट नहीं कर पाता। भुगतान रोकने के कारण चैक जारी करने वाले पर संबंधित बैंक या संस्थाएँ चार सौ से आठ सौ रूपये तक का जुर्माना लगा देती है। मैंने पिछले साल ओरियन्टल इंशोरेंस कंपनी को अपनी मेडिकलम पोलिसी के लिए चैक दिया। चैक बैंक गया तो भुगतान रुक गया। मैं बैंक गया। बैंक प्रबंधक ने खाता देखकर कहा कि खाता आपका जारी है। चैक का भुगतान कैसे रुका पता नहीं। उनके एक स्टाफ ने देखकर बताया कि खाता बंद किया हुआ है। बैंक प्रबंधक ने कहा कि अब सब कॉप्यूटराइज है। हमें पता नहीं चलता और खुद जाता है। बैंक स्टाफ के पता है या नहीं। इससे खाताधारक को क्या लेना। मेरे से तो इंशोरेंस कंपनी ने चैक डिस ओनर होने के छह सौ रूपये अतिरिक्त बसूल लिए। मुझे तो फालतु का छह सौ रूपये का दंड पड़ गया। अपनी लालू आपैन क्यों बैंक जान पाता तो बैंक क्या क्या करे



मसज जाना है एक आवार जायाराइजरान माल्यम से अपन ड्राइवर
लाइसेंस पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराइए। समझ नहीं आ
रहा कि क्या-क्या कराएं। हम पर ये सब करना नहीं आता। इसका
मतलब ये की रोज जनसेवा केंद्र पर जाइये। लाइन में लगिए और
पैसा भी दीजिए। लगता है कि कहीं ये जनसेवा केंद्र की आय बढ़ाने
के लिए तो नहीं किया जा रहा। अभी पिछले दिनों आदेश आया कि
अपना आधार कार्ड प्रयेक दस साल में अपडेट कराना है। मैं छोटे
शहर में रहता हूँ। यहां कि आबादी दो लाख के करीब है। पूरे शहर
में आधार कार्ड अपडेट कराने का एक ही सेंटर है। मुख्य डाकघर।
उसमें आधार कार्ड बनवाने वालों की सर्वेरे आठ बजे से लाइन लग
जाती है। हम 75 साल से ऊपर के पति-पत्नी कैसे उस लाइन में लगें,
ये कोई सोचने और बताने वाला नहीं है। दूसरे केंद्र का दरवाजा
खुलने पर इस तरह धक्का-मुक्की होती है कि हम लाइन में लगे तो
उस संस्थान का अपडेट कराने के लिए हैं।

उसके जीवन को कठिन बना रहे हैं, जबकि उन्हे अपने ग्राहकों सुविधांए देनी चाहिए थीं। ऐसा ही आधार कार्ड अपडेट कराने लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। हाँ इसके लिए उपभोक्ता से थं बहुत चार्ज लिया जा सकता है। अभी एक मैसेज आया कि आप इन्कमटैक्स का रिटर्न स्वीकार कर लिया गया है। मैंने अभी रिभरा नहीं, सो ये मैसेज बेटे को भेज दिया कि शायद उसने रिटर्न नहीं हो। उसका जबाब आया कि पापा इस मैसेज के लिंक पर क्लिक मत करना। ये गलत लगता है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि सभी और गलत का कैसे तय हो। किसी न किसी तरह धोखे में लेकर सभी में नहीं देते नहीं देते हैं। यहाँ ऐसे नहीं हैं। यहाँ देते हैं।

८

શાનદાર પહુલ ઑનલાઇન ગેમિંગ એપ પર સરળ કાનૂન

देश में प्रिंट मीडिया,

एवरपाद, हावड़, सड़क, हवाली जहाज, रस्ता, मट्रो रस्ता, बस आदि भूमि पर साथ भ्रमित करने वाले ऑनलाइन गेमिंग ऐप का प्रचार चर्चित चर्हां के साथ बढ़े पैमाने पर होता नज़र आता है। इन चर्चित चर्हां के प्रमोशन करने के चलते देश में करोड़ों लोग ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से चल रही सट्टेबाजी, ठगी व साइबर फ़ाड आदि का शिकार होकर के अपने जीवन भर की कर्माई गंवाकर मानसिक तनाव में आकर के अनन्यों जीवन तक को समाप्त करने का कार्य कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग की नकेल कसने का कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि ऑनलाइन गेम की मुख्य रूप से दो कैटेगरी मानी जाती है, पहली कैटेगरी में ई-स्पोर्ट्स जिसमें गेम खेलने के लिए किसी भी प्रकार से पैसों का आदान-प्रदान नहीं किया जाता है व दूसरी कैटेगरी में रियल मनी गेम्स में पैसों का लेन-देन होता है, दूसरी कैटेगरी पर ही मोदी सरकार ने अंकुश लगाया है। देश में इंटरनेट की सुलभता से पहुंच होने के चलते ऑनलाइन गेमिंग ऐप का आलम यह हो गया था कि देश के दूरदराज के गांवों से लेकर कस्बों शहरों तक में भी यह लोगों को घर बैठे-बैठे हुए ही सट्टेबाजी करने के लिए प्रेरित करने लगा है, घर की चौपाल से लेकर के गली, मोहल्ले, नुक़ड़ हर तरफ ऑनलाइन गेमिंग ऐप की चर्चा सुनना अब आम बात हो गयी थी। लेकिन नरेद्ध मोदी की सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग की इस गंभीर चुनौती को समय रहते समझने का कार्य करते हुए, 19 अगस्त 2025 को देश के घर-घर में छोटे बड़े-बड़े तक के बीच में भी अपनी पैठ बना चुके ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर नियन्त्रण लगाने के लिए एक कानून ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को कैबिनेट में पारित करवाने का कार्य करते हुए, 20 अगस्त 2025 को चंद मिनटों में ही घनिष्ठ मत से देश दोनों सर्वोच्च सदानों से पास करवाया। हालांकि देश के कुछ लोगों को इस कानून से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिन लोगों के घर ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से चल रही पैसों की सट्टेबाजी के चलते बर्बादी के कगार पर आकर खड़े हो गये हैं, इस सख्त कानून से उन लोगों के बिखरते घर-बार व कारोबार बच जायेंगे। साथ ही जो परिवार इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप के नाम पर चल रही सट्टेबाजी व साइबर फ़ाड आदि का शिकार होकर धन-दौलत यहां तक की परिजनों को भी खो चुके हैं, उन परिजनों को भी संतोष मिलेगा की अब भविष्य में उनकी तरह किसी का घर-परिवार तबाह नहीं होगा। वैसे तो देश में ऑनलाइन गेमिंग ऐप का बहुत बड़ा कारोबार है, देश में इसके ग्राहक छोटे-छोटे बच्चों से लेकर के बड़े-बुरुर्ग तक भी हैं, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले अपने मोबाइल फोन में इन ऑनलाइन गेमिंग के विभिन्न ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन गेम खेलते हुए इनकी भयंकर लत व मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं। वर्ही इन गेम के प्लेटफार्मों पर खुलम्खुलाकर पैसे लगाओं, टीम बनाओं, करोड़ों कमाओं जैसी आवृत्ति करने वाली टैग लाइन के साथ सट्टेबाजी चल रही है, इन प्लेटफार्मों पर लोग कर्माई के ज़िांसें में आकर के जीवन भर की अपनी गाढ़ी कर्माई को गंवाने का काम कर रहे थे। साथ ही देश में जिस तरह से साइबर फ़ाड की घटनाएं ऑनलाइन गेमिंग ऐप के सहरे आये-दिन घटित हो रही हैं, वह चिंतित करने वाली स्थिति है। जिसके चलते ही नरेद्ध मोदी सरकार की ऑनलाइन गेमिंग के इसके कारोबार पर पैनी नज़र बनी हुई थी। उसी कड़ी में वर्षों पहले ही मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर रुपए-पैसों की किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शन पर 1 अक्टूबर 2023 में 28 प्रतिशत और वर्ष 2024-2025 में जीती गयी धनराशि पर 30 प्रतिशत जीएसटी लागू कर दिया था, जिससे सरकार को लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपए सालाना की भारी-भरकम धनराशि जीएसटी के रूप में मिल रही थी। ऑनलाइन गेमिंग के पिछले कुछ वर्षों में लगभग 400 स्टार्टअप भारत में शुरू हुए हैं, वर्ही लगभग 25 हज़ार करोड़ निवेश हुए हैं। लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नगेश्वरन ने खुलासा किया था कि भारतीय हर वर्ष लगभग 1 लाख 20 हज़ार करोड़ रुपए भारी-भरकम धनराशि इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप के चक्र में खर्च कर रहे हैं, जो बहद ही चौंकाने वाली व चिंताजनक स्थिति है। वर्ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया था कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्र में हर वर्ष 45 करोड़ भारतीय 20 हज़ार करोड़ रुपए गंवा देते हैं। वर्ही देश में साइबर सुरक्षा पर पैनी नज़र रखने वाली एजेंसियों ने भी इन ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफार्मों पर सख्ती कर रखी है जो लोगों को नियन्त्रण के लिए देखती है।

